IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# कोविड-19 के पश्चात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का बेरोजगार युवाओं के रोजगार पर प्रभाव

**डॉ. हरिओम अग्रवाल**
**प्राध्यापक (वाणिज्य)**
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सतना (म.प्र.)

**श्रीमती अर्चना सिंह**
**पी. एच.डी. शोधार्थी एवं अतिथि (वाणिज्य)**
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सतना (म. प्र.)

**सारांश:-**

भारत युवाओं का देश है। भारत में 15 से 35 वर्ष के भी 50% से अधिक युवा निवास करते हैं जो कि विश्व के किसी भी देश से सर्वाधिक है। इस प्रकार भारत में जानाकिंकी लाभांश की स्थित प्राप्त है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में इन युवाओं की ऊर्जा का लाभ देश के विकास कार्य में नहीं लग रहा है। सी एम आई ए की रिपोर्ट 2022 के अनुसार शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 10.09 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रमें 7.44 प्रतिशत है। NSO नवंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी 7.2 प्रतिशत है। कोविद-19 के कारण अन्य देशों की तरह भारत को भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है लेकिन भारत सरकार ने देश की विकराल बेरोजगारी को दूर करने के लिए 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पहले वर्ष में 24 लाख युवाओं को शामिल करने की योजना थी जबकि 2022 तक मत संख्या बढ़कर 40 करोड़ तक करने की थी। वर्ष 2021 -22 के दौरान इस योजना के तहत 3 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

शब्द कुंजी (keywords) पी एम के बी आई आई, एनएसडीसी, एनएसओ, जनांकिकीय लाभांश, समावेशी विकास, कौशल विकास।

## प्रस्तावना:-

भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को मुक्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत 2015 -16 मैं 19.85 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था। 31 जुलाई 2017 तक 31.222 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षित किए गए हैं, जिनमें करीब 17 लाख पुरुष एवं 14 लाख महिलाएं हैं। इस योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर,फूड प्रोसेसिंग , फर्नीचर और फिटिंग, जेम्स एवं जेली और लीडर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40

तकनीकी क्षेत्र को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी।

★ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2023 के लिए पत्रताएं भारत का मूल निवासी होना चाहिए।

★ आई का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए ।

★ 10वींव 12वीं पास होना चाहिए।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हेतु दस्तावेज -आधार कार्ड, वोटरकार्ड , पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पास पोर्ट साइज फोटो, बैंक डिटेल।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कोर्स लिस्ट - प्लाविंग कोर्स, रबर कोर्स, रिटेल कोर्स, माइनिंग कोर्स, एंटरटेनमेंट मीडिया कोर्स, लाइफ साइंस कोर्स, सिक्योरिटी सर्विस कोर्स, मोटर वाहन कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक कोर्स, टूरिज्म कोर्स, पवन इंडस्ट्री कोर्स, आईटी कोर्स, निर्माण कोर्स, परिधान कोर्स आदि।

## शोध का उद्देश्य -

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मूल्यांकन करना।
2. बेरोजगार युवाओं पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

## शोध प्राविधि-

यह शोध पत्र तोड़ते हैं द्वितीय समकों पर आधारित है। समकों के संकलन हेतु NSSO की रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, कौशल विकास विभाग की रिपोर्ट, विभिन्न पत्र एवं पत्रिकाओं से संग्रहित किए गए हैं।

## कौशल विकास योजना के लाभ: -

कौशल विकास योजना के प्रारंभ होने से विभिन्न बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं वह अपनी जीवका को चलाने के लिए स्वयं के रोजगार को शुरू कर सकते हैं तथा अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं-

1. राष्ट्रीय आय के साथ- साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि।
2. कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके भारत में बेरोजगारी की समस्या के

निवारण में सहायता मिलेगी।

3. योजना बाद तरीके से गरीबों और गरीबों नौजवानों को संगठित करके उनके कौशल को सही दिशा में प्रशिक्षित करके गरीबों का उन्मूलन करना।
4. देश के युवा जिस कौशल(जैसे गाड़ी चलाना, कपड़े सिलना, अच्छी तरह से खाना बनाना, साफ सफाई करना, मैकेनिक का काम करने, बाल काटना आदि)को परंपरागत रूप से जानते हैं उनके उसे कौशल की गुणवत्ता को बढ़ाकर व प्रशिक्षित करके सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करना है।
5. आने वाले 10 को में पूरी दुनिया में कर कुशल जनसंख्या की आवश्यकता को पूरी करने के लिए विश्व के रोजगार बाजार का अध्ययन करके उनके अनुसार देश के युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र से ही कुशल बनाना।
6. भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या (जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है) कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए कौशल एवं अवसर प्रदान करना।
7. सभी राज्यों और संघ राज्यों को संगठित करके ईट इकाइयों के माध्यम से दुनिया में स्वयं को स्थापित करना।

## प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वर्तमान स्थिति -

नीचे दी गई तालिका के अनुसार सन 2014 से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत 1736 कौशल प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना की गई तथा वर्ष 2017 में यह संख्या बढ़कर 862 हो गई जिसके अनुसार औसतन 3 वर्षों में 125 प्रतिशत की वृद्धि प्रशिक्षण केन्द्रों में हुई। इसी प्रकार वर्ष 2014 में इस प्रशिक्षक केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की संख्या 1954300 थी जो कि वर्ष 2017 में बढ़कर 11725372 होगई, जिसके औसतन 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एक अनुमान के अनुसार प्रशिक्षित युवाओं की संख्या में 3 वर्षों में हुई वृद्धि या दर्शाती है कि प्रधानमंत्री के द्वारा चालू की गई इस योजना का लाभ उठाने की स्थापना में और गति प्रदान की जाए तो और युवा वर्ग इस योजना से लाभान्वित हो सकता है।

**कौशल प्रबंधन केंद्र तथा प्रशिक्षित युवा वर्ग**

| क्रम संख्या | कौशल प्रबंधन केन्द्रों की संख्या | | केन्द्रों की प्रतिशत वृद्धि | एन.एस.डी.सी.परीस्थितिकीय | | ( प्रशिक्षित युवा वृद्धि प्रतिशत ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 मई 1736 | 2017 मई 8662 | 499 प्रतिशत | 2017 11725372 | 2017 11725372 | 600 प्रतिशत |

स्रोत कौशल विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट – 2017

## सुझाव :-

1. कौशल विकास योजना के अंतर्गत ली जाने वाली परीक्षा प्रमाण पत्र एवं उनकी सम्वत्ता की गुणवत्ता में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है।
2. इस योजना के अंतर्गत एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को योजना बाद तरीके से लागू किया जाना चाहिए।
3. सरकार द्वारा अधिकृत संता के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए प्रशिक्षुओ की नगद पारितोषिक की राशि में वृद्धि की जानी चाहिए जिसके फल स्वरुप अधिक से अधिक प्रशिक्षित युवा इस योजना के प्रति आकर्षित हो तथा योजना का लाभ उठा सकें।
4. सरकार को ऐसे माध्यमों का निर्माण करना चाहिए जिसमें कम से कम दस्तावेजों की आवश्यकता हो।
5. राज्य सरकारों को अपने राज्य की भौगोलिक स्थित तथा वातावरण के एंड्रू ऐसी योजना बनाने का अधिकार होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण युवा लाभान्वित हो सके।
6. सुदूर ग्रामीण अंचलों तथा क्षेत्र में ऐसे कौशल प्रशिक्षण/शिक्षा केदो की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है जिसमें आधुनिक संसाधन के माध्यम से शिक्षा दी जा सके।
7. सरकार को इस योजना के तहत पाठ्यक्रमों के बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित की गुणवत्ता का समय-समय पर आकलन करना चाहिए, जिससे युवाओं का सही मार्ग दर्शन हो सके।

## निष्कर्ष-

उपरोक्त विश्लेषण से निष्कर्ष स्वरूप में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से बेरोजगार युवाओं को न सिर्फ ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई है बल्कि स्वराज हेतु प्रेरित किया है। आज बेरोजगार युवा अपना स्वयं का स्टार्टअप खोल रहे हैं। इस योजना का दायरा वर्ष दरवर्ष बढ़ता जा रहा है जो आगे भी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

## संदर्भ ग्रंथ:-

1. दत्त गौरव व महाजन अश्वनी(2016)भारतीय अर्थव्यवस्था एस चंद एंड कंपनी दिल्ली पृष्ठ संख्या 275
2. मिश्रा एस के वी पुरीबी के भारतीय अर्थव्यवस्था हिमालय पब्लिशिंग हापुड़ मुंबई।
3. आर्थिक समीक्षा भारत सरकार वित्त मंत्रालय सार्थक प्रमाण 2020-21
4. योजना पत्रिका 2019
5. कुरुक्षेत्र पत्रिका 2021